

किसानों को मुआवजा देकर हमने अहसान नहीं किया : सीएम

दृजा 5-3 4-4-16

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने किसानों को 20 हजार रुपये एकड़ मुआवजा देकर अहसान नहीं किया बल्कि सरकार ने किसानों को उनका हक देने का अपना काम किया है। किसानों को मुसीबत में उनका ही पैसा वापस किया है। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। मुख्यमंत्री भारतीय किसान यूनियन द्वारा कंझावला में आयोजित किसान मजदूर रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को 500 रुपये के मुआवजे का चेक दिया गया है। यह किसानों का अपमान है। उन्हें किसानों की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है।



कंझावला में आयोजित किसान मजदूर रैली में उपस्थित किसान।

जागरण

उन्होंने इस साल फसल बर्बाद होने पर किसानों को पिछले साल की तरह ही मुआवजा राशि देने की बात कही। साथ ही कहा कि दूसरे राज्यों में किसानों को मुआवजा राशि के चेक दो साल बाद मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में मुआवजा राशि के चेक एक साल में ही बांट दिए गए। इस मौके पर परिवहन मंत्री गोपाल राय, समाज कल्याण विभाग के मंत्री संदीप कुमार, राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौ. ऋषिपाल अम्बावता सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। मुंडका विधायक सुखबीर दलाल और बवाना विधायक वेदप्रकाश ने मुख्यमंत्री से दिल्ली देहात को कृषि का दर्जा देने की

मांग की।

भूमि अधिग्रहण की राशि बढ़ाने में मशवकत : मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के समय किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव ले ली जाती है। एक एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर किसानों को 56 लाख रुपये मिलते थे। इतनी राशि में दिल्ली के किसी कोने में जमीन नहीं मिलती है। हमने इस राशि को बढ़ाकर प्रति एकड़ 3 करोड़ 7 लाख रुपये कर दिया। जिसे अमल कराने में हमें बड़ी मशवकत करनी पड़ी। दरअसल भाजपा ने एलजी के माध्यम से आदेश निरस्त करने का पत्र जारी कर दिया। हमने उनके ही आदेश को निरस्त कर अधिकारियों को

बड़ी राशि से मुआवजा देने का काम शुरू करा दिया। इससे पूरे देश के किसानों की लड़ाई को बल मिला है। दिल्ली के किसानों ने मुख्यमंत्री के सामने कई मुद्दे रखे। जिसमें धारा 81(कृषि भूमि पर निर्माण निषिद्ध कानून) की धारा खत्म करना, गांवों में लाल डोरा बढ़ाना, एक एकड़ भूमि को भी ट्यूबेल कराने की अनुमति, किसानों को बीज और कृषि उपकरण पर सब्सिडी सहित कई मुद्दे शामिल थे। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मुद्दों पर अमल हो गया है। इसके लिए एक सरकार ने एक कमेटी बनाई है। लेकिन उन्होंने कैबिनेट से मुद्दे पास होने के बाद ही कोई घोषणा करने की बात कही।

श्रीधर 4-4-16

प्रकाश, समाचार पर क्लिक